(d) whether Government propose to pay the premium to all the Beedi Workers tor their group insurance; and

(e) if not, the reasons therefor and how Government propose to popularise the scheme amongst the poor Beedi Workers ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR) : (a) Yes, Sir.

(b) The scheme has come into operation from 1-4-1992. Identity card holding beedi workers in the age group 18—60 years who are not covered under the Employees Provident Fund Scheme are insured for a gam of Rs. 3000/- in the case of natural death and Rs. 6000/- in the case of death by accident.

(c) 3,30,000.

(d) The annual premium of Rs. 27/-per beedi workers is paid in equal share from the Beedi Workers Welfare Fund and LICs Social Security Fund.

(e) The scheme is publicised through the Labour Welfare Fund Organisation network in all the regions.

विभिन्न राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

1147. श्री रामसिंह राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कुल कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम-रोजगार केन्द्र में दर्ज हैं;

(ख) रोजगार केन्द्रों से दो वर्षों के भीतर कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है; और

(ग) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके नाम रोजगार केन्द्रों में दस वर्षों से दर्ज होने के बावजूद जिन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) अगस्त, 1992 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण में प्रस्तुत है। (नीचे देखिये)

(ख) रोजगार में लगाए गए ऐसे व्यक्तियों, जिनकी नियुक्ति चालू रजिस्टर पर नाम दर्ज किए जाने की अवधि के आधार पर की गई थी, का वर्गीकरण नहीं रखा जाता है। तथापि, 1990 और 1991 के दौरान देश के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 2.64 और 2.53 लाख थीं।

(ग) चालू रजिस्टर पर नाम दर्ज किए जाने की अवधि के अनुसार व्यक्तियों की संख्या संबंधी आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता है। तथापि, 1988 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दस वर्ष से अधिक की अवधि तक रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 5.83 % रोजगार चाहने वाले पंजीकृत थे।

विवरण

अगस्त, 1992 के अन्त में देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	संख्या
राज्य	
1. आंध्र प्रदेश	3321.6
2. अरुणाचल प्रदेश	5.5
3. असम	1365.2

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	संख्या
4.	बिहार	3600.5
5.	गोवा	102.6
6.	गुजरात	1034.7
7.	हरियाणा	635.2
8.	हिमाचल प्रदेश	478.9
9.	जम्मू और कश्मीर	130.3
10.	कर्नाटक	1485.4
11.	केरल	3799.0
12.	मध्य प्रदेश	2032.7
13.	महाराष्ट्र	3337.6
14.	मणिपुर	203.8
15.	मेघालय	24.3
16.	मिजोरम	36.1
17.	नागालैंड	22.2
18.	उड़ीसा	907.2
19.	पंजाब	734.3
20.	राजस्थान	890.3
21.	सिक्किम*	
22.	तमिलनाडु	3729.4
23.	त्रिपुरा	178.5
24.	उत्तर प्रदेश	2655.3
25.	पश्चिमी बंगाल	5187.7
	संघ शासित प्रदेश	
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.0
27.	चण्डीगढ़	161.4
28.	दादर और नगर हवेली	2.5
29.	दिल्ली	904.4
30.	दमन और दीव	2.5
31.	लक्षद्वीप	6.9
32.	पांडिचेरी	131.1
	योग	37124.0

टिप्पणी :—1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. ऐसा हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं ।